



पेपर लीक पर संसद में घमासान

राज्यसभा में हंगामे के बीच एमएसएमई संशोधन विधेयक 2026 पेश

नई दिल्ली, 28 जुलाई. सात दिन के गतिरोध के बाद लोकसभा में मंगलवार को 2 बजे से पेपर लीक से जुड़े पब्लिक एग्जामिनेशन संशोधन विधेयक, 2026 पर चर्चा हुई. करीब आठ घंटे तक सदन में कार्यवाही चली. इस दौरान पेपर लीक, शिक्षा व्यवस्था और युवाओं के भविष्य को लेकर सत्ता पक्षा तथा विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिली, जिसमें सत्तापक्ष ने विधेयक को परीक्षाओं की पारदर्शिता और युवाओं के हित में उठाया गया सख्त कदम बताया, जबकि विपक्ष ने इसे सरकार की विफलताओं को छिपाने का प्रयास करार देते हुए कहा कि समस्या कानून की नहीं, बल्कि शासन की मंशा और जवाबदेही की है.

वहीं, संसद के मानसून सत्र के दौरान मंगलवार को भी राज्यसभा में विपक्ष के हंगामे का सिलसिला जारी रहा. प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस द्वारा कथित बल प्रयोग के मुद्दे को लेकर विपक्षी सांसदों की नारेबाजी के कारण सदन की कार्यवाही बार-बार बाधित हुई.

सरकार का पक्ष रखा

सदन में सबसे पहले सरकार का पक्ष रखते हुए केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने चर्चा के लिए पेश करते हुए कहा यह विधेयक लोक परीक्षा अधिनियम 2024 में संशोधन करने के लिए लाया गया है. विधेयक, परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता संगठित परीक्षा माफिया के खिलाफ प्रभावी एवं समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करना है.

जुमला देती है सरकार

इमरजेंसी तो नहीं देखी दिल्ली में युवाओं के खिलाफ पुलिस कार्रवाई देखी है, वह किसी इमरजेंसी से कम नहीं थी. युवाओं के आंदोलन के कारण प्रधान जी (धर्मेंद्र प्रधान) को हटाकर प्रधानमंत्री को बचा लिया गया है. सरकार जब डर जाती है, तो झुक जाती है. भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) वचन नहीं देती है, जुमला देती है. सरकार किसकी आंख में धूल झांकने का काम कर रही है.

लाठी चार्ज किसने करवाया

छात्रों पर लाठी चार्ज करने वालों पर कार्यवाही हो. पैलेट गन चलाने की इजाजत किसने दी. एक ऐसे व्यक्ति को शिक्षामंत्री बनाया जो गर्भवती महिला के बलात्कारियों की रिहाई पर सहमत व्यक्ति की. इस पर स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि प्रियंका जी बिना तथ्यों से इस तरह की बातें सदन में ना करें. वही, शिक्षा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा कि मेरे बारे में जो बोला गया उस पर मुझे पहले से नहीं बताया गया।

सदन में कार्यवाही के दौरान सवाल – जबाब

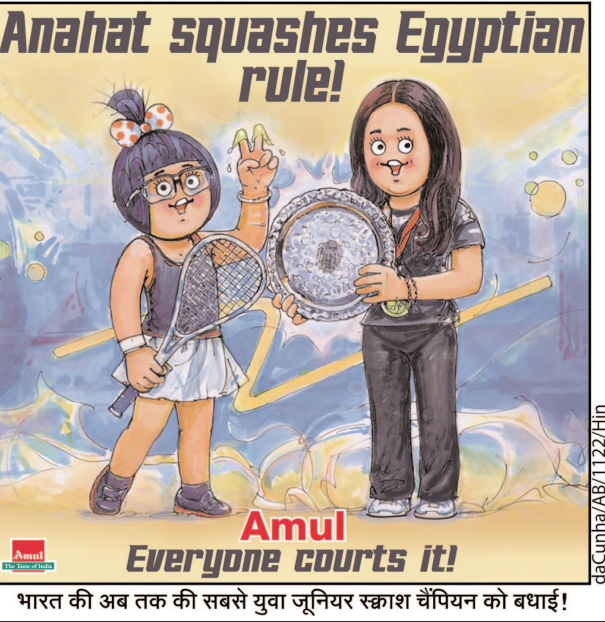
- प्रियंका गांधी ने सदन में शिक्षा मंत्री पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि शिक्षा मंत्री बलात्कारियों का समर्थन करते हैं
- संसद के बाहर लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी ने पत्रकारों से बात करते हुए प्रियंका गांधी समर्थन किया .
- गृहमंत्री अमित शाह से शिक्षा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने मुलाकात भी की है .
- प्रियंका का जवाब- जोशी ने बिल्किश बानो के बलात्कारियों पर बयान दिया उसका प्रमाण में भेज दूंगी।
- केसी वेणुगोपाल ने कहा- इन्होंने इंदिरा गांधी का नाम लिया है। आप हटा नहीं सकते हैं।

परीक्षा–प्रणाली में पारदर्शिता राष्ट्रहित का महत्वपूर्ण विषय

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि परीक्षा-प्रणाली की विश्वसनीयता और पारदर्शिता राष्ट्रहित का महत्वपूर्ण विषय है. इस विषय पर व्यापक चर्चा और गंभीर विचार-विमर्श आवश्यक है. आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, जब सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों विधेयक पर चर्चा के लिए सहमत हुए हैं. पूरा देश वाहता है कि सभी सदस्य इस विषय पर सार्थक विचार-विमर्श करें. अपने अनुभव, सुझाव और प्रह्लाद जोशी ने कहा कि मेरे बारे में जो बोला गया उस पर मुझे पहले से नहीं बताया गया।

जापान में आया 7.1 तीव्रता का भूकंप

टोक्यो, 28 जुलाई. जापान के दक्षिण-पश्चिमी क्यूशू क्षेत्र के कुमामोटो प्रांत में मंगलवार को 7.1 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया. जापान के भूकंपीय तीव्रता पैमाने पर इसकी तीव्रता अधिकतम स्तर शिंदो-7 दर्ज की गयी. इसके बाद मौसम एजेंसी ने अरियाके और यात्सुशिरो सागर के तटीय क्षेत्रों के लिए सुनामी की चेतावनी जारी करते हुए लोगों से समुद्र तटों से दूर रहने की अपील की है. जापान मौसम एजेंसी के अनुसार, भूकंप के तुरंत बाद सुनामी की पहली लहर इन समुद्री क्षेत्रों में पहुंचने की आशंका जतायी गयी है.



हर शुक्रवार जनता के द्वार पहुंचेगी सरकार

मंत्री, विधायक, कलेक्टर और अधिकारी गांव-वार्डों में पहुंचकर सुनेंगे समस्याएं

- 7 अगस्त से पूरे प्रदेश में शुरू होगा जन विश्वास अभियान
- योजनाओं के क्रियान्वयन की होगी जमीनी समीक्षा



प्रशासनिक संवाददाता भोपाल, 28 जुलाई. राज्य सरकार ने जन समस्याओं के त्वरित समाधान और सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए जन विश्वास अभियान शुरू करने का फैसला किया है. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में यह अभियान 7 अगस्त से पूरे प्रदेश में शुरू होगा और हर शुक्रवार संचालित किया जाएगा. अभियान के तहत मंत्री,

जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी गांवों एवं शहरी वार्डों में पहुंचकर आम जनता से सीधे संवाद करेंगे, उनकी समस्याएं सुनेंगे और सरकारी योजनाओं के जमीनी क्रियान्वयन की समीक्षा करेंगे. अधिकारी ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पहुंचकर लोगों की समस्याएं सुनेंगे तथा जहां संभव होगा, वहीं उनका समाधान करेंगे. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट में इस संबंध में निर्णय लिया गया.

(शेष पेज 12 पर)

एक नजर में

दिल्ली में महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 2,500

नई दिल्ली. दिल्ली सरकार ने महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को इसकी घोषणा करते हुए बताया कि इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 2,500 की वित्तीय सहायता सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की जाएगी. यह योजना महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने और उनके जीवन स्तर में सुधार लाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगी.

चीनी की जमाखोरी रोकने तय की भंडारण सीमा

नई दिल्ली. घरेलू बाजार में चीनी की बढ़ती कीमतों के बीच जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए सरकार ने इसके भंडारण की सीमा तय कर दी है. नये नियमों के अनुसार, चीनी का कोई भी डीलर कोई भी स्टॉक 30 दिन से अधिक अपने पास नहीं रख सकेगा. साथ ही चार हजार क्विंटल से अधिक चीनी के भंडारण पर रोक लगा दी गयी है. उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की ओर से मंगलवार को जारी अधिसूचना में कहा गया है कि यह आदेश 01 अगस्त 2026 से चार महीने के लिए जारी रहेगा.



जिनका आपराधिक रिकॉर्ड नहीं उन्हें रिहा करें

- आठ राज्यों को सुप्रीम कोर्ट ने दिए निर्देश
- प्रदर्शनकारियों की व्यक्तिगत जानकारी सार्वजनिक न करें



नई दिल्ली, 28 जुलाई. उच्चतम न्यायालय ने पिछले सप्ताह हुए विरोध प्रदर्शनों में हिस्सा लेने पर गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए उन सभी छात्रों को मंगलवार को रिहा करने का आदेश दिया जिनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है. इसके साथ ही न्यायालय ने केंद्र सरकार और असम, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तथा केरल सरकारों से जवाब मांगा है. वहीं सुप्रीम कोर्ट ने बिना आपराधिक रिकॉर्ड वाले छात्रों को रिहा करने के भी आदेश दिए हैं.

न्यायालय ने यह भी कहा कि राष्ट्रव्यापी छात्र विरोध प्रदर्शनों के दौरान छात्रों और पुलिस कर्मियों को आई चोटों के आरोपों की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच जरूरी है. न्यायालय ने इस मामले में अंतरिम

मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति टी. मोहना की पीठ पुलिस बर्बरता के आरोपों वाली याचिकाओं के साथ-साथ घायल पुलिस कर्मियों और मीडियाकर्मियों द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी. न्यायालय ने छात्र प्रदर्शनकारियों की व्यक्तिगत जानकारी और डिजिटल डेटा को सुरक्षित रखने तथा ऐसी जानकारी को फिलहाल सार्वजनिक न करने का आदेश दिया.

निर्देशों की एक श्रृंखला जारी करते हुए यह भी संकेत दिया कि वह अपने एक पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक विशेष जांच दल का गठन कर सकती है.

लखपति दीदी से 46 करोड़ महिलाओं को मिला लाभ

नई दिल्ली, 28 जुलाई. केंद्र सरकार ने बताया है कि दीनदयाल अन्वोदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत संचालित लखपति दीदी पहल के माध्यम से अब तक देशभर में 46 करोड़ से अधिक स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को लखपति दीदी के रूप में सक्षम बनाया गया है.

इस पहल का उद्देश्य महिलाओं को कम से कम चार कृषि मौसमों और/या व्यावसायिक चक्रों तक सतत आधार पर न्यूनतम एक लाख रुपए वार्षिक आय अर्जित करने में सक्षम बनाना है. ग्रामीण विकास

ग्रामीण बैंकों ने 10,177 करोड़ का अर्जित किया लाभ

देश भर के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) ने वित्त वर्ष 2025-26 में 10,177 करोड़ रुपये का अब तक का सर्वाधिक शुद्ध लाभ अर्जित किया और इनके अन्य प्रमुख वित्तीय मानकों में भी लगातार सुधार दर्ज किया गया है. यह जानकारी वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्य सभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी. उन्होंने कहा कि सरकार नियमित प्रदर्शन समीक्षा, प्रौद्योगिकी उन्नयन तथा वित्तीय समावेशन पहलों के माध्यम से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सशक्त बना रही है. प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना तथा अटल पेंशन योजना के अंतर्गत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की प्रगति की सरकार समय-समय पर समीक्षा करती है.

उन्हें सामाजिक एवं वित्तीय रूप से सशक्त बनाना है. इसके तहत देशभर में 10.08 करोड़ ग्रामीण परिवारों को करीब 92 लाख स्वयं सहायता समूहों में संगठित किया गया है. मध्य प्रदेश में 2,67,520 एसएचजी सदस्यों को लखपति दीदी बनाया गया है, जिनमें छिंदवाड़ा जिले के लगभग 46,000 सदस्य शामिल हैं. मंत्रालय ने बताया कि डीएवाई-एनआरएलएम के तहत स्टार्ट-अप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम (एसवीईपी) के माध्यम से स्वयं सहायता समूहों और उनके परिवारों को गैर-कृषि क्षेत्र में छोटे उद्यम स्थापित करने के लिए सहायता दी जा रही है.

मंत्रालय द्वारा राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों (चंडीगढ़ और दिल्ली को छोड़कर) के सहयोग से संचालित डीएवाई-एनआरएलएम का उद्देश्य गरीब ग्रामीण परिवारों की आजीविका में सुधार करना और



भीषण बवंडर ने अमेरिका में मचाई तबाही

वाशिंगटन, 28 जुलाई. अमेरिका के मिडवेस्ट क्षेत्र में आए शक्तिशाली बवंडर और तेज तूफान ने व्यापक तबाही मचाई है. सबसे अधिक असर विस्कॉन्सिन राज्य में देखने को मिला, जहां 3.9 लाख से अधिक घरों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की बिजली आपूर्ति बाधित हो गई. तूफान के कारण कई इलाकों में पेड़ जड़ से उखड़ गए, बिजली के खंभे और तार क्षतिग्रस्त हो गए तथा अनेक मकानों की छतें उड़ गईं. प्रभावित क्षेत्रों में जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है.

मेटा ने सरकार से मांगी माफी

प्रधानमंत्री मोदी का वीडियो बहाल किया, केंद्र ने किया तलब

नई दिल्ली, 28 जुलाई. इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का वीडियो हटाए जाने के मामले में मेटा के वैश्विक प्रमुख को तलब किया है. इस बीच मेटा ने वीडियो हटाए जाने पर खेद व्यक्त करते हुए कहा है कि यह कार्रवाई तकनीकी त्रुटि के कारण हुई थी और वीडियो को बहाल कर दिया गया है. सूत्रों के अनुसार, केंद्र सरकार इस घटना को गंभीरता से ले रही है और मेटा की ओर से दी

गयी तकनीकी त्रुटि की सफाई के साथ-साथ उन परिस्थितियों की भी जांच कर रही है, जिनके कारण वीडियो हटाया गया. इसी सिलसिले में मंत्रालय ने मेटा (फेसबुक और इंस्टाग्राम) के अधिकारियों को तलब किया है. मेटा के प्रवक्ता ने वीडियो बहाल होने के बाद मंगलवार को जारी एक बयान में कहा, यह सामग्री गलती से हटा दी गयी थी और अब उसे बहाल कर दिया गया है. श्री मोदी का यह वीडियो 23 जुलाई को अपलोड किया गया था.

जिंदगी की नई शुरुआत | मजबूत इरादे और लगातार मेहनत से हर बाधा को कर सकते हैं पार

हरियाणा की बेटी शर्मिला ने घर बेचकर रचा इतिहास

महेंद्रगढ़, 28 जुलाई. हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के चित्रौली गांव की बेटी शर्मिला धनखड़ ने यह साबित कर दिया कि हालात चाहे कितने भी कठिन क्यों न हों, मजबूत इरादे और लगातार मेहनत हर बाधा को पार कर सकते हैं. महिलाओं की पैरा शॉट पुट एफ 57 स्पर्धा में 9.81 मीटर का सीजन बेस्ट थ्रो कर कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली शर्मिला आज पूरे देश के लिए प्रेरणा बन गई हैं. उनका यह स्वर्ण



सिर्फ खेल की उपलब्धि नहीं, बल्कि संघर्ष, साहस और आत्मविश्वास की असाधारण कहानी है. महज दो वर्ष की उम्र में पोलियो की चपेट में आने से

उनका एक पैर प्रभावित हो गया. छोटे किसान परिवार में जन्मी शर्मिला की मां दुष्टिबाधित हैं और आर्थिक तंगी के कारण उनका समुचित इलाज भी नहीं हो सका. कम उम्र में शादी हुई, लेकिन वैवाहिक जीवन ज्यादा समय तक नहीं चला.

26 वर्ष की उम्र में पति ने उन्हें दो बेटियों सहित घर से निकाल दिया. इसके बाद उन्होंने मायके लौटकर जिंदगी की नई शुरुआत की. 28 वर्ष की उम्र में अजीत से दूसरी शादी हुई, जिन्होंने हर

प्रमुख बातें

- पोलियो, गरीबी और संघर्ष को मात देकर कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को दिलाया स्वर्ण पदक.
- दो साल की उम्र में हुआ था पोलियो
- घर बिका, हौसला नहीं; शर्मिला बनी गोल्डन गर्ल
- पति का साथ, बेटियों का हौसला और मेहनत ने बदल दी जिंदगी की तस्वीर.
- 34 साल की उम्र में उन्होंने कोच टेकचंद और देवेंद्र के मार्गदर्शन में एफ 57 कैटेगरी के सीटेंड शॉट पुट इवेंट की ट्रेनिंग शुरू की.

कदम पर उनका साथ दिया और पैरा एथलेटिक्स में करियर बनाने के लिए प्रेरित किया. 34 वर्ष की

उम्र में शर्मिला ने कोच टेकचंद और देवेंद्र के मार्गदर्शन में सीटेंड शॉट पुट की ट्रेनिंग शुरू की.

एक और मौका देने ईरान पर हमला रोका गया : ट्रंप

वाशिंगटन, 28 जुलाई. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने कूटनीति को एक और मौका देने के लिए ईरान के खिलाफ सैन्य हमलों को रोकने का फैसला किया है. इसके साथ ही उन्होंने यह चेतावनी भी दी कि सभी विकल्प मेज खुले हैं और यदि बातचीत विफल होती है तो अमेरिका जल्द ही व्यापक सैन्य कार्रवाई पर लौट आएगा. ट्रंप ने सोमवार को एक्सियोस से बातचीत में कहा कि जारी बातचीत होमुज जलडमरूमध्य



कार्यक्रम पर एक व्यापक समझौते पर फिर से वार्ता शुरू करने पर केन्द्रित है. यह वार्ता मुख्य रूप से ईरान और ओमान द्वारा की जा रही है, जिसमें कतर, पाकिस्तान, मिक्स और ट्रंप के दूत स्टीव वित्कोफ एवं जेरेड कुशनर भी शामिल हैं.